हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला

विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा 28 से 29 जून, 2019 को सिन्धु नदी बेसिन की पाँच प्रमुख नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम) का वानिकी गतिविधियों के माध्यम से पुनरूद्धार करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने हेतु आरम्भिक विचार मंथन कार्यशाला (Launch Workshop) का आयोजन किया गया।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर, माननीय वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार** ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं वन बल प्रमुख, श्री अजय कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं श्री जितेन्द्र शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल व वन बल प्रमुख, पंजाब वन विभाग ने

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. सविता, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश वन विभाग इस समारोह में बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रही। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के मुख्य रूप से वन विभाग तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और हितधारकों सहित हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लगभग 43 विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला एवं विचार–मंथन में भाग लिया।

आरम्भ में संस्थान के प्रभारी निदेशक, श्री सत्य प्रकाश नेगी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों तथा सभी प्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन किया तथा मुख्य अतिथि का इस अवसर पर पधारने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

सर्वप्रथम इस समारोह में डॉ. सविता प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए उनके निर्देशन/अगुवाई मैं तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अवधारणा, प्रक्रिया, मुद्दों व चुनौतियों तथा प्रयोज्यता पर बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी हितधारकों के परामर्शानुसार वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने गंगा नदी के लिए रिवर्सस्केप अवधारणा पर आधारित **अन्नत वन और अविरल धारा** द्वारा पाँच प्रमुख भू–दृश्यों के लिए वानिकी गतिविधियों के प्लांटेशन मॉडल (Plantation Model) का विकास किया। गौरतलब है कि सिन्धु नदी बेसिन की प्रमुख नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में गंगा डी.पी.आर. को मानक के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

इस अवसर पर श्री अजय कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग

हिमाचल प्रदेश व जितेन्द्र शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग पंजाब द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गए तथा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला को इस कार्य के निष्पादन हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

कार्यशाला में पंजाब वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं वन बल

प्रमुख, श्री जितेन्द्र शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वर्तमान समय में नदियों और जल से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंतन का विषय बनें हैं क्योंकि जल संसाधनो में निरंतर हो रही कमी व ह्रास के कारण अगला विश्वयुद्ध

जल संकट के कारण होने की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि यह कार्यशाला सिन्धु नदी बेसिन की प्रमुख नदियों के पुनरूद्धार करने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगी।

कार्यशाला में, उद्घाटन अभिभाषण पर बोलते हुए श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की नदियां, पहाड़ों तथा मैदानी इलाकों में जनसंख्या के एक बड़े भाग की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा अपने जल अधिग्रहण क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पारिस्थितिकी व वनों से सम्बन्धित बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है। उन्होंने नदियों और राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए कहा कि इस कार्य में विभिन्न विभागों की सहभागिता और सहयोग बहुत जरूरी है, उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय संस्कृति में जल, भूमि और वनों की विशेषता है और हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में वनों की अदभूत सम्पदा उपलब्ध होने के कारण डी.पी.आर. तैयार करने में हमारी अग्रणी भूमिका अपेक्षित है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे देशहित के इस कार्य में पूर्ण प्रतिबद्धता, गंभीरता के साथ अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रयोजित सिन्धु नदी बेसिन की प्रमुख नदियों का वानिकी गतिविधियों द्वारा पुनरूद्धार (rejuvenate) करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने का कार्य वास्तव में बहुत प्रासंगिक और व्यवहारिक तथा संस्थान द्वारा आयोजित यह आरम्भिक कार्यशाला व विचार मंथन बैठक आगे बढ़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने इस कार्यशाला में भाग ले रहे सभी सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों व हितधारकों से आहवान किया कि वे इस कार्य के लिए गम्भीर चिंतन कर, महत्वपूर्ण सस्तुतियां व सुझाव पेश करें तथा अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर इस जनहित के कार्य को सफल बनाएं।

अंत में मंत्री महोदय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून तथा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला को इस नेक कार्य के लिए बधाई तथा शुभकामनाएं प्रेषित की साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्थान इस कार्य के निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा तथा उन्होंने राज्य सरकार के सभी सम्बन्धित विभागों, विशेषतः वन विभाग एवं राज्यों के विभिन्न विभागों को इस कार्य में संस्थान का पूर्ण सहयोग करने की अपील की।

समापन अवसर पर, डा. राजेश शर्मा, समूह समन्वयक अनुसंधान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि, गणमान्य अतिथियों, विशेष अतिथियों और सभी प्रतिभागियों का इस आयोजन में भाग लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

डॉ. सविता, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश गंगा नदी के पुनरूद्धार से सम्बन्धित डी.पी.आर. का अनुभव सांझा करते हुए

डा. पी.के. माथुर, डी.पी.आर. तैयार करने बारे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए

डा. ओम बीर सिंह, डी.पी.आर. तैयार करने बारे अपने अनुभव सांझा करते हुए

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी

मीडिया कवरेज

HIMACHAL PRADESH

The Tribune
CHANDIGARH | SATURDAY | 29 JUNE 2019

'Namami Indus' rejuvenation project on cards

All stakeholders from Himachal, Punjab, Jammu & Kashmir and Chandigarh to be roped in

KULDEEP CHAUHAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, JUNE 28

After the "Namami Gange" river rejuvenation project, the Ministry of Forests and Environment and Climate Change has decided to implement the "Namami Indus River" rejuvenation project in a year's time involving all stakeholders from Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir and the Union Territory of Chandigarh.

Inaugurating a two-day workshop of stakeholders for the preparation of a detailed project report (DPR) for the rejuvenation of the Indus river basin project through forestry interventions, Forest Minister Govind Singh Thakur said conservation of water sources of perennial Himalayan rivers of Indus basin — Sutlej, Ravi, Beas, Chenab and Jhelum — was very important. These rivers support and sustain the livelihoods of a large populace of the hill and those living downstream.

Thakur said the water crisis has underscored the need for conservation of the Himalayan rivers, jungle and biodiversity. Like the Namami Gange project, the Indus river system project would become a reality soon as all stakeholders would act as a team for this project.

He said Himachal was trying to increase green forest cover up to 35 per cent. "We will plant 25 lakh green saplings during the five-day Van Mahaotsav this year", he added.

Officiating director, Himalayan Forest Research Institute (HFRI), which organised the workshop, SP Negi said the Centre had directed the institute to complete the DPR of the project in a year time. This workshop would get inputs from all stakeholders, including scientists, NGOs and farmers, who would be benefitted by the project, he added.

PrCCF (Wildlife) , Himachal, Dr Savita cited the implementation of the the Namami Gange project for which the DPR was prepared under her guidance.

Principal Chief Conservator, Forests, Himachal, Ajay Kumar said it was for the first time that the DPR would be focusing on the reduction of discharge of silt in the rivers using forestry interventions.

Principal Chief Conservator, Forests, Punjab, Jitendra Sharma said water security and water politics were going to grow because of depletion of river resources and water scarcity across the country. Indus Basin rejuvenation concern Punjab and other states as most of the fresh water from rains that goes waste, can be stored for recharging by using watershed modes and NGOs.

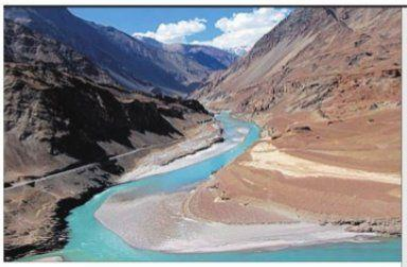

Water crisis has underscored the need for conservation of the Himalayan rivers, jungle and biodiversity.

DPR in one year

- Forest Minister Govind Singh Thakur said conservation of water sources of perennial Himalayan rivers of Indus basin — Sutlej, Ravi, Beas, Chenab and Jhelum is very important.
- These rivers support and sustain the livelihoods of a large populace of the hill and those living downstream.
- Officiating director, HFRI, said the DPR of the project would be completed in a year.

The Tribune Sat, 29 June 2019
https://epaper.tribuneindia.com/c/40860012

Detailed Project Report to be prepared for rejuvenation of Indus basin

SHIMLA, 28 JUNE

Sensitive towards the concern of conservation of water resources, the various stakeholders from the northern region have joined hands to prepare a Detail Project Report for rejuvenation of Indus River basin.

Working in this direction, Himalayan Forest Research Institute (HFRI), Shimla on Friday organised a two-day long launch Workshop and Brainstorming for preparation of DPR for rejuvenation of Indus River through Forestry intervention. The workshop is being attended by various stakeholders from the states of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.

While inaugurating the workshop Forest, Sports and Youth Services Minister Govind Singh Thakur said that the perennial Himalayan Rivers of Indus Basin including Satluj, Ravi, Beas, Chenab and Jhelum, are very important as these rivers support and sustains the livelihoods of a large populace of the hill and downstream plains.

On this occasion, the minister highlighted the cultural and religious significance of Indian River system and said that nature worshipping is the legacy of Indian culture.

He opined that Union and state government are quite concerned about the issues and challenges of nature and natural resources including land, rivers, environments and forests. He further said that the ambitious task of DPR preparation of Indus Basin River is very timely and all the concerned state departments are required to show seriousness for execution of this work and come forward with recommendation and suggestions for this work. He appreciated the initiative being taken by Ministry of Environment (MoE), Forests and Climate Change, Government of India for rejuvenation of nine major Indian river systems through forestry intervention, this includes the Indus River basin also which have five major rivers — Beas, Chenab, Ravi, Sutlej and Jhelum originating and flowing through the states of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. SNS

The Statesman Sat
htt

हिमाचल सवेरा
दैनिक सवेरा tv
www.dainiksaveratimes.com
DAINIK SAVERA TIMES, SHIMLA | शिमला, शनिवार, 29 जून 2019 | /dainiksavera /saveratimes /dainik.savera /dainiksaveravideos

गंगा की तर्ज पर प्रदूषण मुक्त होंगी हिमाचल की नदियां

सरकार ने एचएफआरआई को सौंपा डीपीआर बनाने का जिम्मा, रावी, चिनाव, ब्यास, झेलम व सतलुज होगी प्रदूषण मुक्त

- वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया कार्यशाला का शुभारंग
- एक साल में बन कर तैयार होगी डीपीआर

शिमला, 28 जून (धनंजय शर्मा) : नमामि गंगे की तर्ज पर हिमाचल की जयराम सरकार ने सिंधु नदी बेसिन की पांच नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई है। योजना के तहत हिमाचल की पांच नदियों सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम नदियों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल के साथ पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के वन अधिकारियों ने शुक्रवार को इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला को डीपीआर तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। डीपीआर एक वर्ष के भीतर तैयार की जानी है और इसमें सिंधु नदी बेसिन की वर्तमान स्थिति और अतीत में किए गए नदी प्रबंधन के कार्यों का आकलन के साथ- साथ विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही हितधारकों की पहचान करनाए नदियों के पुनरूद्धार के लिए सर्व सहमति से उचित रूपरेखा विकसित करने के साथ.साथ राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों में नदी प्रबंधन के तहत चल रही वानिकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा वन अ- अधिग्रहण क्षेत्र में पुनर्जनन, पारिस्थितिक तंत्र सुधार की क्षमताओं व संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। साथ ही नदी जल अधिग्रहण क्षेत्र की जैव विविधता व वन प्रकारों की स्थितियों का आकलन किया जाएगा। योजना के तहत इन नदियों में पानी के प्रदूषण को कम कर इसे स्वच्छ बनाया जाना है। डीपीआर में नदियों का वास्तविक स्वरूप बना रहे और भूमि कटाव कम होए इसके लिए भी काम होगा। नदियों की ऊपरी सतह की सफाई के साथ-साथ बहते हुए ठोस कचरे की समस्या का भी समाधान निकाला जाएगा। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को यहां इस कार्य के लिए आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश और विश्व में पानी की जो स्थिति है, उसे देखते हुए हिमालयी राज्यों की पानी को लेकर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब इन नदियों के संरक्षण को लेकर डीपीआर हमें बनानी है तो जिम्मेदारी भी और अधिक बढ़ जाती है। उनका कहना था कि आज जल संरक्षण की सबसे अधिक जरूरत है और इस डीपीआर के बनने से इसमें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन नदियों को लेकर बनने वाली डीपीआर से यह भी पता चलेगा कि किस नदी की आज वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे इनके कैचमैंट को बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार इन्हें बचाया जा सकता है। ठाकुर ने कहा कि राज्य में 20 फीसदी पहाड़ ऐसे हैं जहां 12 माह बर्फ रहती है और राज्य में कुल जंगल का 27 फीसदी वन आवरण है और इसे बढ़ाकर 35 फीसदी करना है।

कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते परिवहन, वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तथा (दाएं) उपस्थित अधिकारी व अन्य लोग। (ओम)

जुलाई व अगस्त माह में शुरू होगा पौधरोपण अभियान

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य में जुलाई और अगस्त माह में पौधरोपण का अभियान शुरू किया जाएगा। वन विभाग ने इस बार टारगेट तय किया है और वह टारगेट 5 दिन में 25 लाख पौधे रोपने का है। उनका कहना था कि इस टारगेट को तय समय में पूरा किया जाएगा और वन विभाग सभी सहयोगी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की मदद से इस पूरा करेगा। इस अभियान का समय आने वाले दिनों में तय किया जाएगा और एक कार्यक्रम बनाकर इस पोधरोपण अभियान को चलाया जाएगा।

दैनिक सवेरा Sat, 29 June 2019
dainiksaveratimes.epapr.in/c/40868093

हिमाचल जागरण
www.jagran.c

गंगा की तर्ज पर वन अनुसंधान संस्थान तैयार करेगा डीपीआर, गंगा नदी रहेगी आधार, हिमाचल व जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हो रही प्रदूषित, कम हो रहा पानी

सिंधु बेसिन की पांच नदियों को मिलेगा नया जीवन

राज्य ब्यूरो, शिमला : सिंधु बेसिन की पांच प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को गंगा नदी की तर्ज पर नया जीवन मिलेगा। यह जीवनदायिनी नदियां अविरल बहती रहें, इसके लिए इनके आसपास के क्षेत्रों में वानिकी कार्य होंगे। इन पर हुए शोध से पता चला है कि ये भी प्रदूषण की जद में आ चुकी हैं। साथ ही इनमें पानी की मात्रा भी कम हो गई है। ऐसे में अब इनका उपचार देकर नया जीवन दिया जाएगा।

इस सिलसिले में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसका आधार गंगा नदी की डीपीआर होगी। इसका जिम्मा शिमला स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआइ) को सौंपा गया है। संस्थान पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। इसे स्वीकृत के लिए मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सतलुज, रावी और ब्यास हिमाचल में बहती हैं, जबकि चिनाब और झेलम जम्मू कश्मीर में सतलुज हिमाचल के बाद पंजाब से होकर गुजरती हैं। पांचों सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनके पुनर्जीवन का काम पहली बार होगा। जलवायु परिवर्तन, मानवीय दखल, विकास गतिविधियों के कारण इनका पानी पहले जैसा शुद्ध नहीं रह गया है। अनुसंधान संस्थानों के शोध के बाद केंद्र सरकार ने तय किया है कि इनका व्यापक उपचार होगा। इसके लिए गंगा जैसा सफाई अभियान भी छेड़ा जाएगा।

शिमला में शुक्रवार को कार्यशाला के दौरान वनमंत्री गोविंद ठाकुर व अन्य ● जागरण

गंगा नदी पर दी प्रस्तुति

पीसीसीएफ वन्य प्राणी डॉ. सविता ने गंगा नदी की डीपीआर पर प्रस्तुति दी। वह अनुसंधान संस्थान देहरादून में कार्यरत थीं। इस डीपीआर को उनकी अगुवाई में तैयार किया गया था। सिंधु बेसिन की नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में गंगा की डीपीआर को मानक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पीसीसीएफ डॉ. अजय कुमार व पंजाब के पीसीसीएफ जितेंद्र शर्मा ने इसमें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। जितेंद्र ने कहा कि नदियों और जल से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंतन का विषय बने हुए हैं।

शिमला में विचार-मंथन आरंभ

नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए प्रारंभिक खाका जल्द खींचा जाएगा। इसके लिए शिमला में विचार मंथन आरंभ हो गया है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में दो दिवसीय आरंभिक विचार मंथन कार्यशाला शुक्रवार को शुरू हुई। इसमें हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के हितधारकों ने भाग लिया। इसमें वन, कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कई महकमों के अधिकारियों व विशेषज्ञों ने विचार रखे। हिमाचल के वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इसमें शिरकत की।

यह कार्यशाला डीपीआर बनाने की दिशा में अहम कड़ी साबित होगी। हिमालयी क्षेत्रों की नदियां पहाड़ सहित मैदानी इलाकों में जनसंख्या के बड़े भाग की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यह अधिग्रहण क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष से पारिस्थितिकी व वनों से संबंधित बहु सारी प्रक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है डीपीआर बनाने में विभिन्न विभागों की सहभागिता और सहयोग जरूरी है।

-गोविंद ठाकुर, वन मंत्री, हिमाचल

केंद्र ने अहम जिम्मेदारी दी है। डीपीआर तैयार करने में कड़ी मेहनत करेंगे। सभ हितधारकों और विशेषज्ञों का सहयोग लेंगे। मंत्रालय के हर निर्देशों की कड़ाई पालना होगा।

-प्रभारी निदेशक, एसपी नेगी, एचएफआरआइ

'नमामि गंगे' की तर्ज पर हिमाचल की नदियां भी होंगी अब स्वच्छ

एचएफआरआई तैयार करेगा डीपीआर, रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञों से हो रही चर्चा, हिमाचल के अलावा जेएंडके की दो नदियों की भी संस्थान बनाएगा डीपीआर

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। गंगा सफाई के बाद अब केंद्र सरकार का फोकस नमामि गंगे की तर्ज पर सिंधु नदी बेसिन की सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियों को स्वच्छ करने का है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने केंद्र के निर्देश पर शिमला स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई) को इन नदियों की सफाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। 18 महीने के अंदर तैयार होने वाली इस रिपोर्ट में नदियों की खुद सफाई की क्षमता को बढ़ाने के अलावा नदी बेसिन की वर्तमान स्थिति, अतीत में किए गए नदी प्रबंधन के कार्यों का आंकलन और विश्लेषण, हितधारकों की पहचान करना और उनकी मदद से नदियों को बचाने के लिए रूपरेखा तैयार करना, नदी जल अधिग्रहण क्षेत्र की जैव विविधता और वन प्रकारों की स्थितियों का आकलन करना शामिल है। हैं। इस डीपीआर को बनाने को संबंधित नदी व छोटे जल विभाजन क्षेत्रों के अलावा सभी सहायक नदियां भी अध्ययन क्षेत्र में शामिल होंगी। संस्थान के प्रभारी निदेशक सत्य प्रकाश नेगी ने बताया कि नदियों और सहायक नदियों का पूरा जल अधिग्रहण क्षेत्र मुख्य नदी के तट के दोनों ओर के पांच किलोमीटर और सहायक नदी के दो किमी वाले बफर जोन के तौर पर चिह्नित कर वानिकी कार्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

लखनऊ के चार बाग से देहरादून का किराया होगा 1220 रुपये

डीपीआर बनाने को दो दिन शिमला में होगी चर्चा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। इस डीपीआर को बनाने के लिए शुक्रवार को संस्थान की ओर से होटल हलांडे होम में दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। पहले दिन वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की नदियां, पहाड़ों तथा मैदानी इलाकों में जनसंख्या के एक बड़े भाग की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन्होंने नदियों और राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए कहा कि इस कार्य में विभिन्न विभागों की सहभागिता और सहयोग बहुत जरूरी है। इस अवसर पर पीसीसीएफ अजय कुमार, पंजाब के पीसीसीएफ जितेंद्र शर्मा, पीसीसीएफ वन्य जीव डॉ. सविता, एचएफआरआई के प्रभारी निदेशक सत्यप्रकाश नेगी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

दो दिवसीय कार्यशाला में बनेगी रणनीति

गंगा की तर्ज पर सिंधु बेसिन की नदियों के कायाकल्प को बन रही योजना

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब व चंडीगढ़ के वन अधिकारियों के अलावा सभी हितधारक विभागों ने तैयार की रूपरेखा

सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदियों की वानिकी गतिविधियां चलाकर कायाकल्प को बनाई जा रही डी.पी.आर.

शिमला, 28 जून (ब्यूरो): गंगा की तर्ज पर सिंधु नदी बेसिन की 5 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है। इसे लेकर शुक्रवार को शिमला में आयोजित कार्यशाला में हिमाचल के अलावा पंजाब, जम्मू-कश्मीर व चंडीगढ़ वन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदियों की वानिकी गतिविधियां चलाकर कायाकल्प करने को लेकर चर्चा की। 2 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ तथा हितधारकों के सुझाव लेकर इन नदियों के जल को स्वच्छ बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्यशाला का उद्घाटन वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम की तर्ज पर प्रदेश से बहने वाली पांचों नदियों के लिए डी.पी.आर. तैयार करना अच्छी पहल है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान (एच.एफ.आर.आई.) के इस प्रयास में वन विभाग वृक्षारोपण करके आहुति डालेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने इस साल जुलाई व अगस्त महीने में 25 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 5 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इनमें कई औषधीय गुणों वाले वृक्ष भी रोपे जाएंगे, जोकि प्रदेश की पांचों प्रमुख नदियों में जल की स्वच्छता को बढ़ाने में मदद करेंगे और वनों पर निर्भर लोगों को आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर पंजाब वन विभाग के पी.सी.सी.एफ. जितेंद्र शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों में निरंतर हो रही कमी के कारण अगला विश्व युद्ध जल संकट के कारण होने का भय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सिंधु नदी बेसिन की प्रमुख नदियों के पुनरोद्धार करने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगी। हिमाचल के पी.सी.एफ. हॉफ डा. अजय कुमार ने कहा कि नदियों के कैचमैंट एरिया में वानिकी गतिविधियों से इनका कायाकल्प संभव होगा। पी.सी.सी.एफ. वन्य जीव डा. सविता ने गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए तैयार की गई डी.पी.आर. की अवधारणा, प्रक्रिया व चुनौतियों की जानकारी प्रदान की। डा. सविता ने कहा कि इन नदियों के कैचमैंट एरिया में औषधीय पौधे लगाकर इनकी अविरल धारा को यूं ही बहते रहने और जल को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। एच.एफ.आर.आई. के निदेशक सत्य प्रकाश नेगी ने कहा कि कार्यशाला में सभी से सलाह-मशविरा लेकर सिंधू बेसिन की पांचों

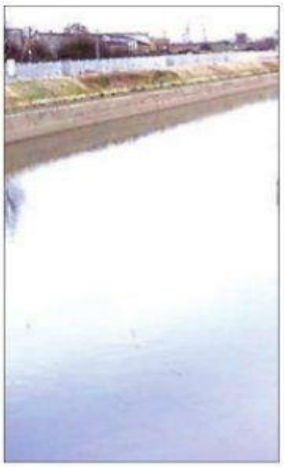

नदियों के कायाकल्प के लिए डी.पी.आर. तैयार की जाएगी।

बाद में इस डी.पी.आर. पर काम करके वन, पर्यावरण और जल को दूषित होने से बचाने की दिशा में काम किया जाएगा।

पांच नदियों के अच्छे दिन

नमामि गंगे की तर्ज पर संवरेंगी सतलुज-ब्यास-रावी-चिनाव-झेलम

विशेष संवाददाता – शिमला

हिमाचल प्रदेश की पांच बड़ी नदियों को नमामि गंगे की तर्ज पर संवारने का काम किया जाएगा। विशेषज्ञों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इन पांच नदियों में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम शामिल हैं। ये पांचों नदियां सिंधु बेसिन की प्रमुख नदियां हैं। नदियों में पानी का प्रदूषण कम कर इसे स्वच्छ बनाने पर महत्त्वपूर्ण काम होगा। नदियों का वास्तविक स्वरूप बना रहे और भू कटाव कम हो, इस दिशा में भी काम किया जाएगा। नदियों की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या भी हल की जाएगी। इसके लिए आम जनमानस का भी सहयोग लेंगे। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य सौंपा है। शुक्रवार को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए पहली वर्कशॉप का शुभारंभ किया। एचएफआरआई संबंधित विभागों, पर्यावरण प्रेमियों और हितधारकों की राय भी डीपीआर बनाने में लेगा। इसके लिए शिमला में दो दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। हिमालयन वन संस्थान के प्रभारी निदेशक सत्य प्रकाश नेगी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीपीआर बनाने में सभी का सहयोग लिया जा रहा है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य जीव डा. सविता ने गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए उनके निर्देशन में तैयार की गई डीपीआर अवधारणाएं प्रक्रिया मुद्दों व चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। प्रधान मुख्य अरण्यपाल डा. अजय कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल पंजाब जितेंद्र शर्मा सहित अन्य ने भी विचार रखे।

- प्रदूषण दूर करने के लिए होगा काम
- विशेषज्ञों का मंथन शुरू

दिव्य हिमाचल Sat, 29 June 2019
https://epaper.divyahimachal.com/c/40859410

शिमला: होटल होलीडे होम में हिमालयन वन अनुसंधान द्वारा नदियों को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर व भाग लेते गणमान्य

दिव्य हिमाचल Sat, 29 June 2019
https://epaper.divyahimachal.com/c/40861597

ठाकुर ने किया दो दिवसीय आरंभिक विचार मंथन कार्यशाला का शुभारंभ

शिमला के होलिडे होम में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान द्वारा सिंधु नदी बेसिन पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए परिवहन, वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। (छाया : धर्मेन्द्र)

कार्यशाला के शुभारंभ के साथ ही डीपीआर बनाने के प्रोजैक्ट का भी शुभारंभ हो गया

शिमला, 28 जून (अ.स.) : वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला में सिन्धु नदी बेसिन की पांच प्रमुख नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम का वानिकी गतिविधियों के माध्यम से पुनर्जीवन करने के उद्देश्य से डीपीआर बनाने के लिए दो दिवसीय आरंभिक विचार मंथन कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला का आयोजन हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यशाला के शुभारंभ के साथ ही डीपीआर बनाने के प्रोजैक्ट का भी शुभारंभ हो गया। यह डीपीआर को बनाने की समय सीमा एक साल निर्धारित की गई है। इस प्रोजैक्ट का मुख्य उद्देश्य नवामी गंगा की तर्ज पर हिमाचल व जेएण्डके की पांच नदियां हैं रिजूविनेट करना है। इस कार्यशाला में हिमाचल, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और हितधारकों सहित करीब 125 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से एकजुट होकर टीम स्पीरिट से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल वन महोत्सव के दौरान 5 दिन में 25 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों तथा मैदानी इलाकों में जनसंख्या के एक बड़े भाग की आजीविका को चलाने में हिमालयी क्षेत्रों की नदियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा अपने जल अधिग्रहण क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पारिस्थितिकी व वनों से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत उत्पादन जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के जल का व्यापक स्तर पर दोहन किया जा रहा है, जिस कारण नदियों में जल प्रवाह में निरंतर कम हो रहा है। वहीं हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक सत्य प्रकाश नेगी ने बताया कि नदियों के पानी का सोर्स, केचमेंट व जंगल में हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण केचमेंट क्षेत्र में दबाव बढ़ा है। इसलिए नवामी गंगा की तर्ज पर नदियों के केचमेंट ऐरिया में वानिकी के माध्यम से पौधारोपण करने तथा उनको पुर्नजीवत करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है, जिससे पानी की गुणवत्ता व मात्रा बढ़े। उन्होंने कहा कि केचमेंट ऐरिया कोट्रिट करेंगे, इससे पानी की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में मंथन किया जाएगा कि किन-किन राज्यों में क्या-क्या किया गया है तथा किस-किस राज्य में क्या करने की संभावना हैं।

अजीत समाचार 29-Jun-2019
Page: 3
उत्तर भारत का सम्पूर्ण अख़बार
http://www.ajitsamachar.com/20190629/8/3/1_1.cms